



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 393]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 1985/भाद्र 11, 1907

No. 393]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 1985/BHADRA 11, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1985

अधिसूचना

सं. 287 /85-सामाशुल्क

सा. का. वि. 705 (अ) :- केन्द्रिय सरकार संभाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 क फं, उपधारा (2) और (3) तथा धारा 9 ख की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सोमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर शुल्क या प्रतिरक्षित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा अति का प्रवधारण) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन का तारख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से सामाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 अभि-
प्रेत है;

(ख) "अभिहित प्राधिकारों" से नियम 3 के अधिन अभिहित प्राधि-
कारों के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) "घरेलू उद्योग" से उस या वैसे ही वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन में या उससे संबंधित किसी क्रियाकलाप में लगे हुए समस्त घरेलू उत्पादक या वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन, उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक पर्याप्त भाग तब के सिवाय बनता है जब ऐसे उत्पादक अधिकथित पाटित वस्तु के निर्यात-कर्ताओं या आयात-कर्ताओं के नातेदार हैं या वे स्वयं उसके आयातकर्ता हैं। ऐसी दशा में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं समझा जाएगा :

परन्तु इन नियमों के नियम 18 के उपनियम (3) में निविष्ट असाधारण परिस्थितियों में, प्रश्नगत वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग में दो या अधिक प्रतियोगी बाजार समाविष्ट समझे जाएंगे और ऐसे प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादकों का एक अलग उद्योग समझा जाएगा यदि :-

(i) ऐसे किसी बाजार के भीतर उत्पादक प्रश्नगत वस्तु का अपने सभ या लगभग सभ उत्पादन का उस बाजार में विक्रय करते हैं ; और

(ii) उस बाजार मांग का, राज्य क्षेत्र में अन्यत्र अवस्थित उक्त वस्तु के उत्पादकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं क जान है;

(घ) "प्रतिपाटन पद्धतियों के संबंध में टैरिफ और व्यापार संबंधों साधारण करार" से तारीख 12 अप्रैल, 1979 के टैरिफ और व्यापार संबंधों साधारण करार के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन संबंधी करार अभिप्रेत है;

(ङ) "हितबद्ध पक्षकार" से ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिस पर आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ता है और जो इन नियमों के अधिन अन्वेषण में हितबद्ध है;

(च) "हस्ताक्षरकर्ता" से ऐसा देश या राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जो टैरिफ और व्यापार संबंधों साधारण करार के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन संबंधी करार का पक्षकार है या जिसको उसने प्रतीकार किया है;

(छ) उन शर्तों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. अभिहित प्राधिकारों के नियुक्ति :— (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के सचिव को या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वह सरकार ठक समझे, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अभिहित प्राधिकार नियुक्त कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार उस अभिहित प्राधिकारों को ऐसे अन्य व्यक्तियों की सेवाएं और ऐसे अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा जो वह ठक समझे।

4. अभिहित प्राधिकारों के कर्तव्य :— (1) इन नियमों के अनुसार अभिहित प्राधिकार का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) किस वस्तु के अधिकारित पाटन का विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव के बारे में अन्वेषण करे ;

(ख) किस शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के लिए दायां वस्तुओं की पहचान करे ; और

(ग) ऐसा वस्तुओं के संबंध में प्रसामान्य मूल्य के बारे में केन्द्रीय सरकार को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करे।

(2) यदि अभिहित प्राधिकार इन नियमों के अनुसार अन्वेषण करने के पश्चात् किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अधिनियम का धारा 9 की उपधारा (i) के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्यातकर्ता देश या राज्यक्षेत्र से भारत की किस वस्तु का उसके प्रसामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया जाता है तो वह केन्द्रीय सरकार को, यथास्थिति, किस ऐसे शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के अन्तर्गत या अन्यथा अधिरोषण के लिए सिफारिश कर सकेगा जो ऐसा वस्तु के संबंध में पाटन अंतर से अधिक नहीं होगा।

परन्तु ऐसे देशों या राज्य क्षेत्रों की दशा में, जो अधिनियम का धारा 9 ख के अधीन राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं, यथास्थिति कोई ऐसा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक अभिहित प्राधिकार ने इन नियमों के अनुसार कोई यह और निष्कर्ष न वे दिया हो कि ऐसी वस्तु का भारत में आयात किया जाना, भारत में स्थापित किसी उद्योग को तात्त्विक अति पहुंचाता है या उसकी खतरा उत्पन्न करता है या भारत में किस उद्योग की स्थापना में तात्त्विक गतिरोध उत्पन्न करता है।

5. अन्वेषण को शामिल करने वाले सिद्धांत :— ऐसी वस्तुओं के पहचान के प्रयोजनों के लिए जो शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के लिए दायां है अभिहित प्राधिकार सभा सुसंगत आनवार और शर्तों के अधिप्राप्त करेगा और वह ऐसे अन्वेषण में निम्नलिखित सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा, अर्थात् :—

(क) कोई वस्तु भारत में पाटन का गई तब समझा जाएगा जब व्यापार के साधारण अनुक्रम में ऐसा वस्तु का निर्यात कम उक्त वस्तु या वैस इ वस्तु के संबंध में प्रसामान्य मूल्य से कम है।

स्पष्ट करण :—

(i) "वैस हूं वस्तु" से अन्वेषण के अधिन वस्तु से सभा बातों में समझ वस्तु और वैस हूं वस्तु के अभाव में, ऐस दूसरा वस्तु अधिप्रेत है जिसकी, यद्यपि वह सभा बातों में वैस हूं नहीं है तो भ, अन्वेषण के अधिन वस्तु का विशेषताओं के अति सद्वा विशेषताएं हैं।

(ii) "निर्यात कम" से निर्यातकर्ता देश से भारत को निर्यात क गई वस्तु का कमत अधिप्रेत है।

6. उद्भव के देश के बारे में विनिश्चय :— यदि किस वस्तु का भारत में उद्भव के देश से आयात नहीं किया जाता है किन्तु किस मध्यवर्ती देश से आयात किया जाता है तो उस क मत का, जिस पर किस वस्तु का मध्यवर्ती देश से विनय किया जाना है, मध्यवर्ती देश में तुल्य क मत से तुलना का जाएगा।

परन्तु ऐस तुलना उद्भव के देश में क क मत से स का जा सकेगा, यदि :

(क) वस्तु का मध्यवर्ती देश के माध्यम से केवल यानांतरण किया जाता है ;

(ख) वस्तु का मध्यवर्ती देश में उत्पादन नहीं किया जाता है ; या

(ग) मध्यवर्ती देश में कोई तुल्य क मत नहीं है।

7. अन्वेषण का शुरू किया जाना :— (1) अभिहित, प्राधिकारों, प्रभावित घरेलू उद्योग से या उसका ओर से किस लिखित अनुरोध का प्राप्ति पर ही प्रसामान्यतया कोई अन्वेषण शुरू करेगा।

(2) अभिहित प्राधिकारों, कोई अन्वेषण शुरू करने का विनिश्चय करने से पहले, अपना यह समाधान करेगा कि उसके पास—

(क) पाटन का,

(ख) टैरिफ और व्यापार संबंधों साधारण करार के अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट मात्रा तक, जहां लागू हो, अति का जैसा कि प्रतिपाटन पद्धतियों के संबंध में टैरिफ और व्यापार संबंधों साधारण करार द्वारा निर्वाचन किया जाए; और

(ग) जहां लागू हो, ऐसे पाटन जायातों और अधिकारित अति के बीच किस आकस्मिक संबंध का, पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य है।

(3) उपनियम (1) में किम बात के होते हुए भ, अभिहित प्राधिकारों कोई अन्वेषण स्वप्रेरणा से शुरू कर सकेगा यदि उसका स मा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधिन नियुक्त स मा-शुल्क कलक्टर से या किस अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी से यह समाधान हो जाता है कि उपनियम (2) में निर्दिष्ट परिस्थितियों की विद्यमानता के बारे में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य विद्यमान है।

8. अन्वेषण की अधिसूचना :— अभिहित प्राधिकारों, कोई अन्वेषण शुरू करने का निश्चय करने के पश्चात् संबंधित निर्यातकर्ता देशों का

सरकारों को ऐसे वस्तुओं के नाम संशुचित करेगा जिन के बारे में ऐसा अन्वेषण किए जाने का प्रस्तावना है।

9. निरीक्षण, प्रतिनिधित्व करने का अवसर— अभिहित प्राधिकारी, किसी हितवद्ध पक्षकार के या संबंधित निर्यातकर्ता देशों की सरकारों के सम्पर्क रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि को—

(क) उनके अनुरोध पर, किसी ऐसे सुसंगत जानकारी का जो उसके पक्ष में है और जो गोपनीय नहीं है, निरीक्षण करने का मुक्तिपत्र अवसर देगा; और

(ख) निश्चित में और पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर, मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

10. गोपनीय जानकारी—(1) किसी अन्वेषण के अनुक्रम में किसी पक्षकार द्वारा अभिहित प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर दी गई कोई जानकारी गुप्तता के बारे में अभिहित प्राधिकारी का समाधान हो जाने पर, उपाय द्वारा गोपनीय माना जाएगा और कोई ऐसा जानकारी, ऐसे पक्षकार के जो ऐसी जानकारी देगा है, विनिश्चित प्राधिकारी के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) अभिहित प्राधिकारी, गोपनीय आधार पर जानकारी देने वाले पक्षकारों से उनके गोपनीय संक्षेप देने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि, ऐसी जानकारी देने वाले किसी पक्षकार की राय में, ऐसी जानकारी का संक्षेप नहीं बनाया जा सकता है तो ऐसा पक्षकार अभिहित प्राधिकारी को ऐसे कारणों का स्पष्ट प्रस्तुत कर सकेगा कि उसका संक्षेप संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अभिहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि गोपनीयता के बारे में अनुरोध करने वाला पक्षकार उसके लिए जो कारण है उन्हें प्रस्तुत करने के लिए राजामंद नहीं है तो अभिहित प्राधिकारी ऐसी जानकारी की अद्वैतता कर सकेगा।

11. अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के राज्य क्षेत्र में अन्वेषण—(1) अभिहित प्राधिकारी अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के राज्यक्षेत्रों में अन्वेषण कर सकेगा यदि किसी मामले की परिस्थितियों से ऐसा आवश्यक हो, परन्तु यह तब जब कि अभिहित प्राधिकारी ऐसे हस्ताक्षरकर्ताओं की सरकारों को पहले ही संशुचित कर देता है। और ऐसे हस्ताक्षरकर्ता अन्वेषणों के बारे में आक्षेप नहीं करते हैं।

(2) अभिहित प्राधिकारी किसी वाणिज्यिक संगठन के परिसरों में भी अन्वेषण कर सकेगा और उसके अभिलेखों की परीक्षा कर सकेगा, यदि ऐसा संगठन सहमत हो जाता है और यदि हस्ताक्षरकर्ता को, जिसके राज्यक्षेत्र में उक्त वाणिज्यिक संगठन स्थित है, यह अधिसूचित कर दिया जाता है और उसमें ऐसे अन्वेषण के किए जाने के बारे में कोई आक्षेप नहीं किया है।

12. प्रारम्भिक निष्कर्ष—अभिहित प्राधिकारी, अन्वेषण करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगा और समुचित मामलों में प्रारम्भिक निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

13. अंतिम शुल्क केन्द्रीय सरकार किसी भी समय किसी वस्तु पर, यथास्थिति, अंतिम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित कर सकेगी, यदि अभिहित प्राधिकारी, उसके उपनियम सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर, प्रारम्भिक निष्कर्ष करता है कि ऐसी वस्तुओं के संबंध में पाटन किया जाता है जो अन्वेषण की विषय वस्तु हैं।

परन्तु किसी ऐसे अन्वेषण की दशा में जिसको धारा 9ख लागू होती है, यथास्थिति, कोई भी अंतिम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक अभिहित प्राधिकारी उसको उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर किसी ऐसे और निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है

कि इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि ऐसी वस्तु का आयात किया जाना, टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार के अनुच्छेद 6 के अर्थ के अंतर्गत भारत में स्थापित किसी उद्योग की तात्त्विक क्षति पहुँचा रहा है या उसका खतरा उत्पन्न कर रहा है या भारत में किसी उद्योग की स्थापना में तात्त्विक गतिरोध उत्पन्न कर रहा है जैसा कि प्रतिपटन पद्धतियों के संबंध में टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार द्वारा निर्वाचन किया जाए और, यथास्थिति, अंतिम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क, अन्वेषण की अवधि के दौरान पहुँचाई गई क्षति को रोक्ने के लिए आवश्यक है।

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, ऐसा कोई अंतिम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क अंतिम रूप से प्राक्कलित ऐसे पाटन अंतर से अधिक नहीं होगा जो निर्यात कीमत और प्रामाण्य मूल्यों के बीच का अंतर होगा।

14. सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर निष्कर्ष—यदि कोई हितवद्ध पक्षकार या हस्ताक्षरकर्ता, अभिहित प्राधिकारी को मुक्तिपत्र अवधि के भीतर पहुँच करने से इंकार करता है या उसका अन्वेषण आवश्यक जानकारी नहीं देता है या उसका अन्वेषण में अड़चन डालता है तो अभिहित प्राधिकारी अपने को उपनियम जानकारी के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा और किरोर सरकार को ऐसी विचारितों कर सकेगा जो यह परिस्थितियों के अधीन ठीक समझें।

15. अन्वेषण को समाप्त या निवृत्त—(1) अभिहित प्राधिकारी अपने विवेकानुसार किसी अन्वेषण को किसी भी समय निलम्बित या समाप्त कर सकेगा—

(क) यदि वह ऐसे प्रभावित करने वाले उद्योग की ओर से, जिसके अनुरोध पर अन्वेषण शुरू किया गया था, ऐसा करने के लिए लिखित में अनुरोध प्राप्त करता है, या

(ख) जब किसी अन्वेषण के अनुक्रम में, अभिहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पाटन का या जहाँ लागू हो, क्षति का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जिससे कि अन्वेषण चालू रखा जाना न्यायोचित ठहराया जा सके।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, अभिहित प्राधिकारी किसी अन्वेषण को निलम्बित या समाप्त कर सकेगा यदि प्रसंगत वस्तु के निर्यातकर्ता—

(क) अभिहित प्राधिकारी को कीमतों का पुनरीक्षण करने के लिए लिखित में बचनबंध करते हैं ताकि उक्त वस्तु का पाटित कीमत पर भारत में कोई निर्यात न किया जा सके, या

(ख) ऐसे देशों की दशा में, जिनको अधिनियम की धारा 9ख लागू होती है, कीमतों को पुनरीक्षण करने या बचनबंध करते हैं ताकि पाटन का हानिकारक प्रभाव कम किया जा सके;

परन्तु ऐसे बचनबंध के परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि उक्त कीमत से उच्चतर नहीं होगी जो पाटन अंतर को कम करने के लिए आवश्यक है।

(3) उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन कीमत वृद्धि से संबंधी कोई बचनबंध, इस नियमों के उपबंधों के अनुसार अभिहित प्राधिकारी द्वारा किसी अन्वेषण के शुरू किए जाने से पहले किसी निर्यातकर्ता से प्रतिगृहीत नहीं किया जा सकेगा और किसी निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्थापित ऐसा बचनबंध, अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रतिगृहीत नहीं किया जाएगा यदि वह उसके प्रतिगृहण को किसी अन्य कारण से असाध्य या अश्रुति-गृहीणीय समझता है।

(4) जहाँ अभिहित प्राधिकारी ने उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन कोई बचनबंध प्रतिगृहीत किया है व जहाँ किसी ऐसे निर्यातकर्ता से, जिससे ऐसा बचनबंध प्रतिगृहीत किया गया है, समय समय पर,

बचनबंध के पूरा किए जाने से सुसंगत जानकारी देने और सुसंगत आंकड़े का सत्यापन अनुज्ञात करने का अनुरोध कर सकेगा :

परन्तु किसी बचनबंध के किसी अतिश्रमण की दशा में, अभिहित प्राधिकारी अपने को उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर, यथास्थिति अन्तिम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित कर सकेगा ।

(5) अभिहित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या प्रश्नगत वस्तु के निर्यात-कर्ताओं या आयातकर्ताओं से या किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त किसी अनुरोध के आधार पर, समय समय पर, पहले ही दिए गए किसी बचनबंध को बालू रखे जाने की आवश्यकता का पुनरीक्षण करेगा ।

16. अंतिम निष्कर्ष :—अभिहित प्राधिकारी किसी अन्वेषण के शुरू किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार असाधारण मामलों में मंजूर करे, इस बात के बारे में अवधारण करेगा कि अन्वेषण के अधीन वस्तु भारत में पाटिल की गई है या नहीं और यदि हाँ तो निम्नलिखित के बारे में निष्कर्ष देगा—

(क) उक्त वस्तु की निर्यात कीमत, प्रसामान्य मूल्य और पाटन मंत्र, और

(ख) ऐसे देशों की दशा में, जिनको अधिनियम की धारा 9ख लागू होती है, क्या उक्त वस्तुओं का भारत में आयात किया जाना, भारत में स्थापित किसी उद्योग को तात्त्विक क्षति पहुँचाता है या उसका खतरा उत्पन्न करता है या भारत में किसी उद्योग की स्थापना में तात्त्विक गतिरोध उत्पन्न करता है ।

17. पाटन का अवधारण :—(1) कोई वस्तु पाटिल की गई समझी जाएगी यदि वह किसी देश या राज्यक्षेत्र से भारत को उसके प्रसामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात की जाती है ।

(2) किसी वस्तु के संबंध में प्रसामान्य मूल्य का अवधारण करते समय, अभिहित प्राधिकारी, विक्रय काराधान और ऐसी अन्य बातों के जो कीमत मुख्यता को प्रभावित करती है निम्नधनों और शर्तों के अंतर के लिए या गुणागुण के आधार पर युक्तियुक्त मीके देगा ।

18. क्षति का अवधारण :—(1) अधिनियम की धारा 9ख की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित देशों या राज्यक्षेत्रों की दशा में, यथास्थिति कोई शुल्क या अतिरिक्त शुल्क अधिनियम का धारा 9क के अधीन तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक अभिहित प्राधिकारी ऐसे किसी और निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि ऐसी वस्तु का भारत में आयात किया जाना भारत में स्थापित किसी उद्योग को तात्त्विक क्षति पहुँचाता है या उसका खतरा उत्पन्न करता है या भारत में किसी उद्योग की स्थापना में तात्त्विक गतिरोध उत्पन्न करता है ।

(2) जब क्षति का कोई निष्कर्ष उपनियम (3) के अर्थान निकलता है तब ऐसे निष्कर्ष में ऐसे तथ्यों की परीक्षा अंतर्बलित होगी जिन्हें अभिहित प्राधिकारी परिस्थितियों के अधीन सुसंगत समझें जिनके अंतर्गत पाटिल आयातों की मात्रा और जैसे हों उत्पादों के लिए बरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे उत्पादों के बरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामिक प्रभाव है ।

(3) अभिहित प्राधिकारी असाधारण मामलों में क्षति की विद्यमानता के बारे में इस बात के होते हुए भी निष्कर्ष दे सकेगा कि बरेलू उद्योग के पर्याप्त भाग को क्षति नहीं हुई है यदि—

(1) पाटिल आयातों का किसी एकल बाजारों में संकेक्षण है, और

(2) पाटिल वस्तुएं ऐसे बाजार के भीतर सभी या लगभग सभी उत्पादन के उत्पादकों को क्षति पहुँचा रही है ।

19. अंतिम निष्कर्ष के परिणाम :—(1) अभिहित प्राधिकारी अपना अन्वेषण पूरा कर लेने पर केन्द्रीय सरकार को अपने अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा ।

(2) यदि ऐसा अंतिम निष्कर्ष जित्त पर अभिहित प्राधिकारी पहुँचता है, तत्कारात्मक है अर्थात् ऐसे प्रथमदृष्टया साक्ष्य के प्रतिज्ञ है, जिसके आधार पर अन्वेषण शुरू किया गया था तो अभिहित प्राधिकारी अन्वेषण को तुरंत समाप्त कर देगा और केन्द्रीय सरकार संबंधित पक्षकार को संग्रहण किया गया कोई अंतिम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क वापस कर देगा ।

(3) यदि अभिहित प्राधिकारी का अंतिम निष्कर्ष तत्कारात्मक अर्थात् ऐसे प्रथम दृष्टया साक्ष्य को पुष्टि करता है कि जित्त के आधार पर अन्वेषण शुरू किया गया था तो केन्द्रीय सरकार प्रश्नगत वस्तु का प्रसामान्य मूल्य अवधारित करेगी ।

20. लोक सूचना :— अभिहित प्राधिकारी निम्नलिखित में संश्लिप्त सभी आवेशों को राजपत्र में प्रकाशित कराएगा ।

(क) शुरू किया जाना,

(ख) अन्वेषण का निर्वहन या समाप्ति,

(ग) ऐसे मामलों में प्रारंभिक निष्कर्ष जिन में अन्तिम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के अधिरोपित किए जाने का प्रस्थापना है ; और

(घ) अंतिम निष्कर्ष

21. शुल्क का अधिरोपण और संग्रहण :— (1) केन्द्रीय सरकार नियम 20 के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा अंतिम निष्कर्षों के प्रकाशन से छह मास के भीतर अंतिम निष्कर्ष के अंतर्गत आने वाला वस्तु के भारत में आयात पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित कर सकेगी जो ऐसी कीमत जिस पर ऐसी वस्तु का भारत को निर्यात किया जाता है और ऐसे प्रसामान्य मूल्य के जो नियम 19 के उपनियम (3) के अर्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए बीच के अंतर से अधिक नहीं होगा ।

(2) इस प्रकार अधिरोपित कोई शुल्क या अतिरिक्त शुल्क अवका नियम 13 और उपनियम (1) के अर्थान अधिरोपित कोई अन्तिम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क और पक्षपूर्ण आधार पर होगा और ऐसी वस्तु के सभी आयातों को लागू होगा चाहे वे किसी भी स्तर से पाटिल की जाएँ और जहाँ लागू हों क्षति पहुँचाते हैं सिवाय उन स्तरों के आयातों का दशा में जिन से नियम 15 के उपनियम (2) के निबंधनों के अनुसार बचनबंध प्रतिगृहित किए गए हैं ।

22. प्राकलित और अंतिम रूप में निर्धारित शुल्क के निक्षेप के बीच अंतर का उपाहार :— (1) यदि अभिहित प्राधिकारी द्वारा किए गए अन्वेषण के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित शुल्क या अतिरिक्त शुल्क पहले हों अधिरोपित और संगृहीत अन्तिम शुल्क से उच्चतर है तो अंतर का आयातकर्ता से संग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् नियम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क पहले हों अधिरोपित या संगृहीत अन्तिम शुल्क का अतिरिक्त शुल्क से निम्नतर है तो अंतर का आयातकर्ता को वापस किया जाएगा ।

23. पुनरीक्षण :— अभिहित प्राधिकारी समय समय पर यथास्थिति शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के निरंतर अधिरोपण की आवश्यकता का पुनरीक्षण करेगा और यदि उसका अपने को प्राप्त ऐसी जानकारी के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के निरंतर अधिरोपण के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं है तो केन्द्रीय सरकार को उसके वापस दिए जाने की सिफारिश करेगी ।

[मि. सं. 528/74/82--सीमा शुल्क (टी.यू.) II]

आर. एम. सिद्धू, अधीक्षक सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 1985

No. 287/85-CUSTOMS

G.S.R. 705(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of section 9A and sub-section (3) of section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) "Act" means the Customs Tariff Act, 1975;
- (b) "designated authority" means the person appointed as designated authority under rule 3;
- (c) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture or production of the same or like articles and any activity connected therewith, or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry;

Provided that in exceptional circumstances referred to in sub-rule (3) of rule 18 of these rules, the domestic industry in relation to the article in question, shall be deemed to comprise two or more competitive markets and the producers within each of such market a separate industry if,—

- (i) the producers within such a market sell all or almost all of their production of the article in question in that market; and
- (ii) the demand in the market is not in any substantial degree supplied by producers of the said article located elsewhere in the territory;
- (d) "GATT Agreement on Anti-dumping Practices" means the agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade dated the 12th April, 1979;

(e) "interested party" means a party who is economically affected and is interested in the investigation under these rules;

(f) "signatory" means a country or territory which is a party to or has acceded to the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade;

(g) words and expressions used in these rules, but not defined, shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Appointment of designated authority.—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint the Secretary to the Government of India in the Ministry of Commerce, or such other person as that Government may think fit, as the designated authority for purposes of these rules.

2. The Central Government may provide to the designated authority the services of such other persons and such other facilities as it deems fit.

4. (1) It shall be the duty of the designated authority in accordance with these rules—

- (a) to investigate as to the existence, degree and effect of any alleged dumping of any article;
- (b) to identify the articles liable for any duty or additional duty; and
- (c) to submit its findings to the Central Government as to the normal value in relation to such articles.

(2) If the designated authority arrives at a finding after conducting investigation in accordance with these rules, that for purposes of sub-section (1) of section 9A of the Act that any article exported from an exporting country or territory to India is at less than its normal value, it may recommend to the Central Government provisionally or otherwise the imposition of a duty, or as the case may be, an additional duty not exceeding the margin of dumping in relation to such article :

Provided that, in the case of countries or territories which have been notified in the Official Gazette under section 9B of the Act, no such duty or additional duty, as the case may be, shall be imposed unless the designated authority has given a further finding in accordance with these rules that import into India of such article causes or threatens to cause material injury to any industry established in India or materially retards the establishment of any industry in India.

5. Principles governing investigation.—For purposes of identifying the articles which will be liable for duty or additional duty, the designated authority shall obtain all relevant information and data and shall be guided in such investigation by the following principles namely :—

- (a) an article shall be considered as being dumped into India if the export price of the article in the ordinary course of trade is less than the normal value in relation to the said article or like article.

Explanation :—

- (i) "like article" shall mean an article identical in all respects to the article under investigation and in absence of a like article, another article which, though not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the article under investigation;
- (ii) 'export price' shall mean the price of the article exported from the exporting country to India.

6. Decision as to country of origin.—In a case where an article is imported into India not from the country of origin but from an intermediate country, the price at which the article is sold from the intermediate country shall be compared with the comparable price in the intermediate country :

Provided that a comparison may also be made with the price in the country of origin if,—

- (a) the article is only trans-shipped through the intermediate country,
- (b) the article is not produced in the intermediate country or,
- (c) there is no comparable price in the intermediate country.

7. Initiation of investigation.—(1) The designated authority shall normally initiate an investigation only upon receipt of a written request by or on behalf of the affected domestic industry.

(2) The designated authority shall, before deciding to initiate an investigation, satisfy itself that it has sufficient prima facie evidence of—

- (a) dumping,
- (b) injury, where applicable, to the extent referred to in Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade as interpreted by the GATT Agreement on Anti-dumping Practices, and
- (c) where applicable, a causal link between such dumped imports and the alleged injury.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the designated authority may initiate an investigation suo moto, if it is satisfied from information received from the Collector of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any other source that sufficient prima facie evidence exists as to the existence of the circumstances referred to in sub-rule (2).

8. Notification of investigation.—The designated authority shall, after deciding to initiate an investigation, communicate to the governments of the exporting countries concerned, names of the articles which are proposed to be subjected to such investigation.

9. Opportunity to inspect, represent.—The designated authority shall allow the duly authorised representative of an interested party or the governments of the exporting countries concerned—

- (a) upon their request, a reasonable opportunity to inspect any relevant information that is in its possession which is not confidential; and
- (b) an opportunity to represent their views in writing, and on sufficient cause shown, orally.

10. Confidential information.—(1) Any information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of an investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summaries thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted, or if the party requesting confidentiality is not willing to submit the reasons therefor, it shall be open to the designated authority to disregard such information.

11. Investigation in the territory of other signatories.—(1) The designated authority may carry out investigations in the territories of other signatories if the circumstances of a case so warrant, provided that the designated authority communicates to the governments of such signatories in advance and such signatories do not object to the investigations.

(2) The designated authority may also carry out investigations at the premises of any commercial organisation and may examine its records if such organisation agrees and if the signatory in whose territory the said commercial organisation is situated, is notified and has not raised any objection for the conduct of such investigation.

12. Provisional duty.—The designated authority shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and shall, in appropriate cases, record a preliminary finding.

13. Provisional duty.—The Central Government may impose at any time, a provisional duty or an additional duty, as the case may be, on an article if, the designated authority makes, on the basis of best information available to it, a preliminary finding that there is dumping in respect of articles which are the subject matter of the investigation:

Provided that in the case of an investigation to which section 9B of the Act applies, no provisional duty or additional duty as the case may be, shall be imposed unless the designated authority arrives at a further finding on the basis of best information available to it, that there is sufficient evidence of the import of such article causing or threatening to cause materially injury to any industry established in India or materially retarding the establishment of any

industry in India within the meaning of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade as interpreted by the GATT Agreement on Anti-dumping Practices and that the provisional duty or additional duty, as the case may be, is necessary to prevent injury being caused during the period of investigation :

Provided further that no such provisional duty or additional duty, as the case may be, shall exceed the provisionally estimated margin of dumping which shall be the difference between the export price and the normal value.

14. Findings on the basis of best information.—In a case in which an interested party or a signatory refuses access to, or otherwise does not provide necessary information to the designated authority within a reasonable period, or impedes its investigation, the designated authority may record its findings on the basis of the information available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under the circumstances.

15. Termination or suspension of investigation.—(1) The designated authority may, at its discretion, suspend or terminate an investigation at any time—

- (a) if it receives a request in writing for doing so on behalf of the domestic industry affected at whose instance the investigation was initiated, or,
- (b) when, in the course of an investigation, the designated authority is satisfied that there is not sufficient evidence of dumping or, where applicable, injury to justify continuation of the investigation.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the designated authority may suspend or terminate an investigation if the exporters of the article in question,—

- (a) give to the designated authority an undertaking in writing to revise prices so that no exports are made to India of the said article at dumped prices, or,
- (b) in the case of countries to which section 9B of the Act applies, undertake to revise the prices so that injurious effect of dumping is eliminated :

Provided that increase in prices as a result of such undertakings is not higher than what is necessary to eliminate the margin of dumping.

(3) No undertaking as regards price increase under clause (b) of the sub-rule (2) shall be accepted from any exporter before the initiation by the designated authority of an investigation in accordance with the provisions of these rules and no such undertaking offered by any exporter shall be accepted by the designated authority if it considers acceptance thereof as impracticable or as unacceptable for any other reason.

(4) Where the designated authority has accepted any undertaking under clause (b) of sub-rule (2), it

may request any exporter from whom such undertaking has been accepted, to provide from time to time information relevant to the fulfilment of the undertaking and to permit verification of relevant data :

Provided that in the case of any violation of any of the undertakings, the designated authority may impose provisional duty or additional duty, as case may be, on the basis of best information available to it.

(5) The designated authority shall suo moto or on the basis of any request received from exporters or importers of the article in question or any other interested person review from time to time the need for the continuance of any undertakings given earlier.

16. Final finding.—The designated authority shall, within one year from the date of initiation of an investigation, or within such extended time as the Central Government may grant in exceptional cases, determine as to whether or not the article under investigation is being dumped in India and if so, give a finding as to—

- (a) export price, normal value and the margin of dumping of the said article and,
- (b) in the case of countries to which section 9B of the Act applies, whether import of the said article into India cause or threaten to cause material injury to any industry established in India or materially retards the establishment of any industry in India.

17. Determination of dumping.—(1) An article shall be considered as being dumped if it is exported from a country or territory to India at less than its normal value.

(2) While determining the normal value in relation to an article, the designated authority shall make reasonable allowance on merits for the differences in terms and conditions of sale, taxation and other factors affecting price comparability.

18. Determination of injury.—(1) In the case of countries or territories notified under sub-section (2) of section 9B of the Act, a duty or additional duty, as the case may be, shall not be imposed under section 9A of the Act, unless the designated authority arrives at a further finding that the import of such article into India causes or threatens to cause material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India.

(2) When a finding of injury is arrived at under sub-rule (3), such finding shall involve an examination of the facts which the designated authority considers relevant under the circumstances including the volume of dumped imports and their effect on prices in the domestic market for like products and the consequent impact of such imports on domestic producers of such products.

(3) The designated authority, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury

even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if—

- (i) there is a concentration of dumped imports into an isolated market and,
- (ii) the dumped articles are causing injury to the producers of all or almost all of the production within such market.

19. Results of final finding.—(1) The designated authority shall, on completion of its investigation submit to the Central Government its final findings.

(2) If the final finding arrived at by the designated authority is negative, that is contrary to the prima facie evidence on whose basis investigation was initiated, the designated authority shall terminate investigation forthwith and the Central Government shall refund any provisional duty or additional duty collected, to the party concerned.

(3) If the final finding of the designated authority is in the affirmative, that is, confirming the prima facie evidence on whose basis investigation was initiated, the Central Government shall determine the normal value of the article in question.

20. Public notice.—The designated authority shall cause to be published in the Official Gazette, all orders relating to the—

- (a) initiation,
- (b) suspension or termination of investigation,
- (c) preliminary findings in cases where provisional duty or additional duty is proposed to be imposed, and
- (d) final findings.

21. Imposition and collection of duty.—(1) The Central Government may, within six months of the publication of the final findings by the designated authority under rule 21, impose by notification in the

Official Gazette upon importation into India of the article covered by the final finding, a duty, or additional duty, which shall not exceed the difference between the price at which such article is exported to India and the normal value as determined by the Central Government under clause (3) of rule 19.

(2) Any duty of additional duty so imposed or a provisional duty or additional duty imposed under rule 13, and sub-rule (1), shall be on a non-discriminatory basis and applicable to all imports of such article, from whatever source found dumped and where applicable, causing injury except in the case of imports from those sources from which undertakings in terms of sub-rule (2) of rule 15 have been accepted.

22. Treatment of difference between deposit of estimated and finally assessed duty.—(1) If the duty or additional duty imposed by the Central Government on the basis of the final findings of the investigation conducted by the designated authority is higher than the provisional duty already imposed and collected, the differential shall not be collected from the importer.

(2) If, the duty or additional duty fixed after the conclusion of the investigation is lower than the provisional duty or additional duty already imposed and collected, the differential shall be refunded to the importer.

23. Review.—The designated authority shall, from time to time, review the need for continued imposition of the duty or additional duty, as the case may be, and shall, if it is satisfied, on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty or additional duty, recommend to the Central Government for its withdrawal.

[F. No. 528/74/82-Cus.(TU)(II)]

R. S. SIDHU, Under Secy.